समक्ष उजागर सिंह न्यायमूर्ति

राजिंदर सिंह, -याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

आपराधिक दुराचार. 1987 का क्रमांक 490-एम.

28 सितम्बर 1987.

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (1954 का XXXVII) - धारा 13 नमूना निदेशक को भेजा गया - ऐसा नमूना टूटा हुआ पाया गया - निदेशक ने विश्लेषण से इनकार कर दिया - अभियुक्त का बचाव – क्या प्रतिकूल है।

अभिनिर्धारित किया गया कि निदेशक ने नमूने को विश्लेषण के लिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि नमूना पार्सल के बाहरी आवरण की सील क्षतिग्रस्त स्थिति में थी। अदालत सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट पर अड़े नहीं रह सकी। सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट को चुनौती देने का एकमात्र तरीका केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा नमूने का परीक्षण कराना था। याचिकाकर्ता को निदेशक से टीएचपी नमूना परीक्षण कराने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है और इसलिए, यह उसके बचाव के लिए हानिकारक है।

(पैरा 6 और 7).

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका। प्रार्थना करते हुए कि आदेश दिनांक 1 नवंबर, 1986 अनुबंध पी/3 और याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप अनुबंध पी/4 को रद्द कर दिया जाए।

प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जे.एम.आई.सी, जगाधरी की अदालत में लंबित कार्यवाही पर, याचिका लंबित रहने के दौरान, रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता के वकील एच. एन. मेहतानी।

रणधीर सिंह, ए.ए.जी. हरियाणा प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

उजागर सिंह, माननीय न्यायमूर्ति

याचिकाकर्ता की दुकान पर 14 दिसंबर, 1983 को खाद्य निरीक्षक सी.एल. सीकरी द्वारा छापा मारा गया था, जिनके साथ चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए.के. सेठी और मोहिंदर सिंह, अभियोजन पक्ष के गवाह, भी थे। वहां 4 पॉलिथीन बैग में आयोडीन युक्त नमक पड़ा हुआ था. उसी में से एक नमूना भुगतान के विरुद्ध, रसीद के माध्यम से, खाद्य निरीक्षक द्वारा लिया गया था। नोटिस आदि की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नमूना सार्वजनिक विश्लेषक को भेजा गया और उसकी रिपोर्ट एग्जिबिट पीडी ने आवश्यकताओं का उल्लंघन दिखाया। खाद्य निरीक्षक द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत एग्जिबिट पीई दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश हुआ और एक नमूना निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद को भेजने के लिए आवेदन किया। स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से नमूना मंगवाया गया और विश्लेषण के लिए निदेशक को भेजा गया। 28 मार्च 1984 की रिपोर्ट के अनुसार यह नमूना टूटा हुआ पाया गया था, हालांकि नमूने और कंटेनर पर सील बरकरार थी। निदेशक को विश्लेषण के लिए तीसरे नमूने की आवश्यकता थी जिसे न्यायालय ने 18 मई, 1984 को तलब किया था और उसे विश्लेषण के लिए निदेशक के पास भेजा गया था। फिर से, निदेशक ने, अपने आदेश दिनांक 12 जुलाई, 1987 के तहत, विश्लेषण के लिए नमूना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि नमूना पार्सल के बाहरी आवरण की सीलें क्षतिग्रस्त थीं।अंततः, ट्रायल कोर्ट को सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट पर ही संतोष करना पड़ा। विस्तृत चर्चा के बाद और विभिन्न प्राधिकारियों के संदर्भ में, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि किसी भी कारण से, निदेशक द्वारा कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था, तो सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा दी गई रिपोर्ट उसमें निहित तथ्यों का सबूत रहती है और यह अप्रभावी नहीं होती, क्योंकि इसे निदेशक के प्रमाणपत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता था। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, यह नहीं माना जा सकता कि सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट एग्जिबिट पीडी को हटा दिया गया है। इसे देखते हुए, याचिकाकर्ता पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 7

के साथ पठित धारा (16) (1) (ए) (i) के तहत आरोप लगाया गया था, - 8 नवंबर, 1986 के आदेश के तहत। उसी दिन उन पर आरोप तय कर दिया गया.

(2) इस आदेश (अनुलग्नक पी3) और आरोप (अनुलग्नक पी4) को इस आपराधिक विविध में चुनौती दी गई है।

(3) विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि कारण जो भी हो, यदि स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास रखे गए दो नमूने परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं, तो अभियुक्त अधिनियम की धारा 13 के तहत अपने अधिकार से वंचित हो जाता है। जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, उन्होंने निर्णय किए गए मामलों का हवाला दिया है, और अपने विचार के लिए उन मामलों से समर्थन मांगा है। राज्य की ओर से विद्वान वकील ने ***नगर निगम दिल्ली बनाम धीसा राम***,[1] मामले से समर्थन मांगा है और तर्क दिया है कि यदि अभियोजन पक्ष की कोई गलती नहीं है और निदेशक की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, तो रिपोर्ट एग्जिबिट पीए का कोई सवाल ही नहीं है और उस पर न्यायालय द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती।

(4) मैंने पार्टियों द्वारा उद्धृत फैसलों पर विचार किया है और उनकी मदद से आदेश और आरोप का अध्ययन किया है।

(5) मुनिसिपल कॉरपोरेशन के मामला में, माननीय न्यायमूर्ति ने निम्नानुसार निर्धारित हैं:-

"हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हर मामले में जहां केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा अपने नमूने का परीक्षण कराने का विक्रेता का अधिकार कुंठित है, विक्रेता को जनतक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हम मानते हैं कि सिद्धांत को, हालांकि, उन मामलों पर लागू किया जाना चाहिए जहां अभियोजन के आचरण के परिणामस्वरूप विक्रेता को इस अधिकार का प्रयोग करने के किसी भी अवसर से वंचित कर दिया गया है। यदि अभियोजन पक्ष जिम्मेदार नहीं है और कोई अनय कारणों से अधिकार निराश हो जाता है तो अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं।"

उस मामले में, उसमें बताई गई घटना के अनुसार, प्रतिवादी-अभियुक्त को बरी करना उचित ठहराया गया था। उसमें मुख्य तर्क यह था कि चूंकि नमूना विश्लेषण के लिए भेजने में देरी हुई, इसलिए वह विघटित हो गया था और परीक्षण

[1] ए आई आर 1967 एस सी 970

के लिए उपयुक्त नहीं रह गया था। उस स्थिति में, यह माना गया कि आरोपी पूर्वाग्रह से ग्रसित था और निदेशक द्वारा नमूने का परीक्षण कराने के अधिकार से वंचित था। यह माना गया कि अभियोजन पक्ष ने विश्लेषण में देरी करने में चूक की है, लेकिन एक चेतावनी है कि यदि अभियोजन जिम्मेदार नहीं है और अन्य कारणों से अधिकार बाधित हो जाता है, तो अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं। ***गुरबचन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले***[2] में, खाद्य निरीक्षक द्वारा रखा गया तीसरा नमूना भेजा गया था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा उत्पादित बोतल अच्छी स्थिति में नहीं पाई गई, क्योंकि उसकी सामग्री कुछ हद तक लीक हो गई थी और निदेशक की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अभियुक्त के अधिकार को पूर्वाग्रह से ग्रसित माना गया और यह माना गया कि अभियुक्त को अपराध के लिए दोषी ठहराना सही नहीं था। ***हजारा सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले***[3] में, गुरबचन सिंह के मामले को मानते हुए (सुप्रा): -

"अभियोजन पक्ष का यह वैधानिक दायित्व था कि वह दूध के तीसरे नमूने, जो पारगमन में टूटा नहीं था, को केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता को भेजते समय ऐसी सावधानियां बरतते हुए आरोपी को निदेशक द्वारा दूध के नमूने का परीक्षण कराने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाए। लेकिन चूंकि अभियोजन पक्ष उस वैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा, इसलिए आरोपी-याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उस नमूने का परीक्षण केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता के निदेशक द्वारा कराने के अपने मूल्यवान वैधानिक अधिकार से वंचित हो गया। "

प्रभु दयाल बनाम हरियाणा राज्य में,[4] यह फिर से माना गया कि यदि नमूना बोतल टूटी हुई पाई जाती है, तो यह माना जा सकता है कि आरोपी को उसके मूल्यवान अधिकार से वंचित कर दिया गया है और इसलिए, अधिनियम की धारा 16(1)(ए)(आई) के तहत अपराध के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(6) ट्रायल कोर्ट के समक्ष, चार फैसलों को संदर्भित किया गया था, वे हैं (i) जोगिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य,[5] (ii) पंजाब राज्य बनाम रमेश कुमार,[6] (iii) नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य,[7] और (iv) छोटू मल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य,[8] और जोगिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) और छोटू मल के मामले (सुप्रा) में उल्लिखित फैसलों पर भरोसा करने के बजाय, ट्रायल कोर्ट ने 1951-1982 (खाद्य अपमिश्रण और औषधि मामलों की रोकथाम के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एक संग्रह) एफएसी (एससी) 93 पर भरोसा किया है। इस फैसले पर मेरे द्वारा पहले ही ऊपर चर्चा की

---

[2] 1972 पी एल आर 771

[3] (1973-77) स सीएलआर 392

[4] (1972) (II) सी एल आर 580

[5] 1984 (2) सी एल आर 353

[6] 1985 (2) एल ए सी 189

[7] 1984 (2) एल एल सो 85

[8] 1981 सी एल आर 576

जा चुकी है और यह एआईआर 1967 एससी 970 के बराबर है। इस फैसले में जो कहा गया था उसे ऊपर दोहराया गया है और ट्रायल कोर्ट ने इस फैसले पर बारीकी से गौर नहीं किया। जोगिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) में, प्रीतपाल सिंह, जे. ने विशेष रूप से माना कि दूसरा नमूना भेजने में देरी से आरोपी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप नमूना विघटित हो गया और इसका विश्लेषण केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा नहीं किया जा सका और उन परिस्थितियों में, यह माना गया कि खाद्य निरीक्षक की शिकायत पर याचिकाकर्ता के मुकदमे को जारी रखना निश्चित रूप से अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। हालाँकि तथ्य मौजूदा मामले से थोड़े अलग थे, फिर भी आरोपी के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह के सिद्धांत को कायम रखा गया है। छोटू माई के मामले (सुप्रा) में निम्नानुसार देखा गया: -

"निदेशक ने बताया था कि उन्हें भेजा गया 'नमूना छाप सील' उस कंटेनर की सील से मेल नहीं खाता था जिसमें तेल का नमूना उन्हें भेजा गया था। ट्रायल कोर्ट ने आपत्ति बरकरार रखी और कहा कि निदेशक की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट पर भरोसा किया और अपीलकर्ता को दोषी ठहराया।"

यह स्पष्ट है कि दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 13(3) के तहत, सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट को केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस प्रकार हटा दिए जाने के बाद, सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट पर दोषसिद्धि का आधार बनाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। सील से छेड़छाड़ के कारण केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक के प्रमाणपत्र को विचार से बाहर कर दिया गया, अदालत के सामने वास्तव में कोई सबूत नहीं था जिसके आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराया जा सके। न्यायालय सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट पर दोबारा विचार नहीं कर सका क्योंकि उसे हटा दिया गया था। सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट को चुनौती देने का एकमात्र तरीका केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा नमूने का परीक्षण कराना था। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को बिना किसी गलती के उस अवसर से वंचित कर दिया गया जिसका वह हकदार था। इसलिए, अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट पर भरोसा करना अदालत के लिए खुला नहीं था..."

ट्रायल कोर्ट ने जोगिंदर सिंह और छोटू मल (सुप्रा) के मामलों को नजरअंदाज करके गंभीर गलती की, हालांकि उनके सामने इसका हवाला दिया गया था और उन्होंने अपने आदेश में इन निर्णयों का उल्लेख किया है।

(7) इस मामले में, मेरी राय है कि आरोपी याचिकाकर्ता को निदेशक से नमूना परीक्षण कराने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है और इसलिए, अपने बचाव में पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया है।

अत: यह याचिका स्वीकार की जाती है। आदेश एग्जिबिट P3 और चार्ज Ex. P4 को रद्द कर दिया गया है। याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शिवदेव शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अम्बाला,हरियाणा